



# महाराष्ट्र शासन राजपत्र

## प्राधिकृत प्रकाशन

वर्ष ६, अंक १९]

गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३०, २०२० / आश्विन २-८, शके १९४२

[पृष्ठे १२, किंमत : रुपये ८.००

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.

### भाग एक-अ-अमरावती विभागीय पुरवणी

(भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.

भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ९२.

#### नगर विकास विभाग

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०२०.

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६.

#### शुध्दीपत्र

क्र. टीपीएस-२७१८-१३९३-प्र.क्र. ११७-२०१८-ई.पी.प्रसिध्दी-नवि-३०.—

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख “उक्त अधिनियम” असा करण्यात आला आहे) चे कलम ३१ पोट-कलम (१) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने अधिसूचना क्र. टीपीएस-२७१८-१३९३-प्र.क्र.११७-२०१८-नवि-३०, दिनांक ५ ऑगस्ट, २०१९ (यापुढे ज्याचा उल्लेख “उक्त अधिसूचना” असा करण्यात आला आहे.) द्वारे प्रारूप सुधारित विकास योजना नेर-नबाबपूर ला अधिसूचने सोबतचे परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविलेल्या फेरबदलासह आणि सूचना क्र. टीपीएस-२७१८-१३९३-प्र.क्र. ११७-२०१८-ई.पी. प्रसिध्दी -नवि-३०, दिनांक ५ ऑगस्ट, २०१९ (यापुढे ज्याचा उल्लेख “उक्त सूचना” असा करण्यात आला आहे.) द्वारे परिशिष्ट-ब मध्ये दर्शविलेले सारभूत स्वरूपाचे फेरबदल वगळता मंजुरी दिली आहे ;

आणि, ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३१, पोट-कलम (१) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने सूचना क्र. टीपीएस-२७१८-१३९३-प्र.क्र. ११७-२०१८-ई.पी. प्रसिध्दी -नवि-३०, दिनांक ५ ऑगस्ट, २०१९ द्वारे उक्त सूचने सोबतचे परिशिष्ट-ब मध्ये नमूद केलेल्या सारभूत स्वरूपाच्या प्रस्तावित फेरबदल (ई.पी.) संदर्भात जनतेकडून हरकत/सूचना मागविण्यात आल्या आहेत ;

आणि, ज्याअर्थी, उक्त सूचने सोबतचे परिशिष्ट-ब मध्ये काही टंकलेखनाच्या त्रुटी व चुका असल्याचे निदर्शनास आले आहे. आणि त्याकरीता सोबत जोडलेल्या जोडपत्रामध्ये नमूद केलेले शुध्दीपत्रक निर्गमित करणे आवश्यक आहे.

त्याअर्थी, आता, उक्त सूचने सोबतचे परिशिष्ट-ब मध्ये अशी सुधारणा करण्यासाठी सोबतच्या जोडपत्रामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे शुध्दीपत्रक निर्गमित करण्यात येत आहे. आणि त्यासाठी शासन याद्वारे :—

- शुध्दीपत्रकात नमूद केलेल्या प्रस्तावित सुधारणा (ई.पी.) चे अनुषंगाने सुधारित विकास योजना नेर-नबाबपूर बाबत सदरहू सूचना शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासून ३० दिवसांच्या कालावधीत किंवा अधिप्रमाणित ई.पी. नकाशे प्रसिध्द केल्या पासून ३० दिवस यापैकी जो उशीरा असेल त्या कालावधीत जनतेकडून हरकती/सूचना मागविण्यासाठी सूचना देत आहे.

२. वरील (१) मधील विहीत मुदतीत प्राप्त होणा-या हरकती/सूचनांवर सुनावणी देऊन पुढील उचित कार्यवाहीसाठी व शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी, सहसंचालक, नगर रचना, अमरावती विभाग, अमरावती यांची उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ (२) अन्वये अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे.

**जोडपत्र**

सुधारीत नेर-नबाबपूर विकास योजनेच्या सारभूत स्वरूपाचे फेरबदलाच्या सूचना क्र.-२७१८-१३९३-प्र.क्र. टीपीएस-११७-२०१८-ई.पी. प्रसिध्दी -नवि-३०, दिनांक ५ ऑगस्ट, २०१९ सोबतचे परिशिष्ट-ब (ई.पी.) ला शुध्दीपत्रक

| सारभूत<br>फेरबदलाचे वर्णन | स्तंभ क्र. ३, ५ किंवा ६ मधील मजकुराऐवजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | असे वाचावे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (१)                       | (२)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (३)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EP-6                      | स्तंभ<br>क्र. ६<br>The land bearing S. No. 12 (p) is proposed to be deleted from Site No. 49-Play Ground and land so released is proposed to be included in Residential Zone as shown on plan.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | The land bearing S. No. 220 (p) is proposed to be deleted from Site No. 49-Play Ground and land so released is proposed to be included in Residential Zone as shown on plan.                                                                                                                                                                                                                               |
| EP-8                      | स्तंभ<br>क्र. ३<br>Site No. 9 Town Hall S. No. 238 (p), 239 (p), 245 (p) Mouje-Ner<br><br>स्तंभ<br>क्र. ५<br>The land bearing S. No. 238 (p), 239 (p), 245 (p) is deleted from Site No. 9-Town Hall and proposed to be included in Residential Zone as shown on plan.<br><br>स्तंभ<br>क्र. ६<br>The land bearing S. No. 238 (p), 239 (p), 245 (p) is proposed to be deleted from Site No. 9-Town Hall and land so released is proposed to be included in Residential Zone as shown on plan. | Site No. 9 Town Hall S. No. 238 (p), 239 (p), Mouje-Ner<br><br>The land bearing S. No. 238 (p), 239 (p), is deleted from Site No. 9-Town Hall and proposed to be included in Residential Zone as shown on plan.<br><br>The land bearing S. No. 238 (p), 239 (p), is proposed to be deleted from Site No. 9-Town Hall and land so released is proposed to be included in Residential Zone as shown on plan. |
| EP-10                     | स्तंभ<br>क्र. ३<br>Existing Library S. No. 367(p) Mouje-Ner<br><br>स्तंभ<br>क्र. ५<br>The land bearing S. No. 367 (p), is to be deleted from Exsting Library and the land so released is proposed to be included in Commercial Zone as shown on plan.<br><br>स्तंभ<br>क्र. ६<br>The land bearing S. No. 367 (p), is deleted from Exsting Library and the land so released is included in Commercial Zone as shown on plan.                                                                  | Existing Library G. No. 358 (p) Mouje-Ner<br><br>The land bearing G. No. 358 (p), is to be deleted from Exsting Library and the land so released is proposed to be included in Commercial Zone as shown on plan.<br><br>The land bearing G. No. 358 (p), is proposed to be deleted from Exsting Library and the land so released is proposed to be included in Commercial Zone as shown on plan.           |
| EP-17                     | स्तंभ<br>क्र. ३<br>Site No. 57 Ware House S. No. 135 (p), Mouje-Nababpur<br><br>स्तंभ<br>क्र. ५<br>The land bearing S. No. 135 (p), is deleted from Site No.57-Ware House and proposed to be included in Agriculture Zone as shown on plan.<br><br>स्तंभ<br>क्र. ६<br>The land bearing S. No. 135 (p), is proposed to be deleted from Site No.57-Ware House and land so released is proposed to be included in Agriculture Zone as shown on plan.                                           | Site No. 57 Ware House S. No. 202, 203, Mouje-Nababpur<br><br>The land bearing S. No. 202, 203 is deleted from Site No.57-Ware House and proposed to be included in Agriculture Zone as shown on plan.<br><br>The land bearing S. No. 202, 203 is proposed to be deleted from Site No.57-Ware House and Land so released is Proposed to be included in Agriculture Zone as shown on plan.                  |

उक्त सूचनेच्या शुध्दीपत्रकाची प्रत जनतेच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात कार्यालयीन वेळेमध्ये उपलब्ध राहिल.

१. सहसंचालक, नगर रचना, अमरावती विभाग, अमरावती, निलगिरी, डॉ. अग्रवाल इमारत, विजय कॉलोनी, कॉंग्रेस नगर रोड, अमरावती-४४४ ६०६.
२. सहाय्यक संचालक, नगर रचना, यवतमाळ शाखा, प्रशासकीय इमारत, तळ मजला, जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर, यवतमाळ.
३. मुख्याधिकारी, नेर-नबाबपूर नगर परिषद, जि. यवतमाळ.

सदर शुध्दीपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या [www.maharashtra.gov.in](http://www.maharashtra.gov.in) कायदे व नियम या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

वीणा मोरे,  
अवर सचिव.

भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ९३.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT  
Mantralaya, Mumbai-400 032, dated 27<sup>th</sup> February, 2020.

THE MAHARASHTRA REGIONAL & TOWN PLANNING ACT, 1966.

#### CORRIGENDUM

No.TPS-2718-1393-CR-117-2018-E.P. Publish-UD-30.—

Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") The State Government *Vide* Notification No. TPS-2718-1393-CR-117-2018-UD-30, dated 5<sup>th</sup> August, 2019 (hereinafter referred to as "the said Notification") has accorded sanction to the Draft Revised Development Plan of Ner-Nababpur with Modifications Shown in Schedule-A, excluding the substantial modifications shown in Schedule-B *vide* Notice No. TPS-2718-1393-CR-117-2018-E.P. Publish-UD-30, dated 5<sup>th</sup> August, 2019 (hereinafter referred to as "the said Notice") appended to the said Notification;

And whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 31 of the said Act, the State Government *vide* Notice TPS-2718-1393-CR-117-2018-E.P. Publish-UD-30, dated 5<sup>th</sup> August, 2019 have invited objections and suggestions from any person in respect of proposed modifications of substantial nature which are excluded from sanction as Excluded Part (E.P), as specified in Schedule-B appended to the said Notice;

And whereas, it is noticed that there are some Typographical errors and mistakes in the said Schedule-B appended with the said Notice and for that purpose it is necessary to issue a Corrigendum for the same as mentioned in Annexure appended hereto.

Now, therefore, this Corrigendum is issued in respect of such corrections in Schedule-B as mentioned in Annexure appended hereto and for that purpose Government hereby;

1. Gives Notice for inviting Objections and Suggestions from any person in respect of proposed substantial modifications (E.P) shown in this Corrigendum within 30 days from the date of publication of this notice in the *official gazette* regarding Revised Development Plan Ner-Nababpur or within the period of 30 days from the date on which authenticated E.P plan is published, whichever is later.
2. Appoints the Join Director of Town Planning, Amravati Division, Amravati as the officer under Section-3 (2) of the said Act to hear any person filing Suggestions/Objections as stated in (1) above

within the stipulated period and to submit his report thereupon to the Government further necessary action.

ANNEXURE

**Corrigenda to Modification in Schedule-B of proposing Excluded Part of Revised Development Plan Ner-Nababpur vide Notification No. TPS-2718-1393-CR-117-2018-E.P. Publish-UD-30, Dated 5<sup>th</sup> August, 2019.**

| Description<br>Sanctioned<br>Excluded<br>part<br>(1) | For the matter under Column No. 3,5 or 6<br>(2)                                                                                                                                                          | Read as<br>(3)                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EP-6                                                 | Column No. 6 The land bearing S. No. 12 (p) is proposed to be deleted from Site No. 49-Play Ground and land so released is proposed to be included in Residential Zone as shown on plan.                 | The land bearing S. No. 220 (p) is proposed to be deleted from Site No. 49-Play Ground and land so released is proposed to be included in Residential Zone as shown on plan.        |
| EP-8                                                 | Column No. 3 Site No. 9 Town Hall S. No. 238 (p), 239 (p), 245 (p) Mouje-Ner                                                                                                                             | Site No. 9 Town Hall S. No. 238 (p), 239 (p), Mouje-Ner                                                                                                                             |
|                                                      | Column No. 5 The land bearing S. No. 238 (p), 239 (p), 245 (p) is deleted from Site No. 9-Town Hall and proposed to be included in Residential Zone as shown on plan.                                    | The land bearing S. No. 238 (p), 239 (p), is deleted from Site No. 9-Town Hall and proposed to be included in Residential Zone as shown on plan.                                    |
|                                                      | Column No. 6 The land bearing S. No. 238 (p), 239 (p), 245 (p) is proposed to be deleted from Site No. 9-Town Hall and land so released is proposed to be included in Residential Zone as shown on plan. | The land bearing S. No. 238 (p), 239 (p), is proposed to be deleted from Site No. 9-Town Hall and land so released is proposed to be included in Residential Zone as shown on plan. |
| EP-10                                                | Column No. 3 Existing Library S. No. 367(p) Mouje-Ner                                                                                                                                                    | Existing Library S. No. 358 (p) Mouje-Ner                                                                                                                                           |
|                                                      | Column No. 5 The land bearing S. No. 367 (p), is to be deleted from Existing Library and the land so released is proposed to be included in Commercial Zone as shown on plan.                            | The land bearing G. No. 358 (p), is to be deleted from Existing Library and the land so released is proposed to be included in Commercial Zone as shown on plan.                    |
|                                                      | Column No. 6 The land bearing S. No. 367 (p), is deleted from Existing Library and the land so released is included in Commercial Zone as shown on plan.                                                 | The land bearing S. No. 358 (p), is proposed to be deleted from Existing Library and the land so released is proposed to be included in commercial Zone as shown on plan.           |
| EP-17                                                | Column No. 3 Site No. 57 Ware House S. No. 135 (p), Mouje-Nababpur                                                                                                                                       | Site No. 57 Ware House S. No. 202, 203, Mouje-Nababpur                                                                                                                              |
|                                                      | Column No. 5 The land bearing S. No. 135 (p), is deleted from Site No. 57-Ware House and proposed to be included in Agriculture Plan Zone as shown on plan.                                              | The land bearing S. No. 202, 203 is deleted from Site No. 57-Ware House and proposed to be included in Agriculture Zone as shown on plan.                                           |

## ANNEXURE—Contd.

| (1)          | (2)                                                                                                                                                                         | (3)                                                                                                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Column No. 6 | The land bearing S. No. 135 (p), is proposed to be deleted from Site No.57-Ware House and land so released is proposed to be included in Agriculture Zone as shown on plan. | The land bearing S. No. 202, 203 is proposed to be deleted from Site No.57-Ware House and land so released is proposed to be included in Agriculture Zone as shown on plan. |

Copy of this Corrigendum is made available for the inspection of the public in the following offices during office hours on all working days.

- Joint Director of Town Planning, Amravati Division, Nilgiri, Dr. Agrawal Building, Vijay Colony, Congress Nagar Road, Amravati-444 606.
- Assistant Director of Town Planning, Administrative Building, Ground Floor, near Collector Office premises, Yavatmal.
- The Chief Officer, Ner-Nababpur Municipal Council, District Yavatmal.

The Corrigendum to the notification shall also be available on the Government website at [www.maharashtra.gov.in](http://www.maharashtra.gov.in). (Acts & Rules).

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

VEENA MORE,  
Under Secretary.

भाग १-अ (अ. वि. पु.), म. शा. रा., अ. क्र. ९४.

### सदस्य सचिव, प्रस्ताव छाननी समिती तथा प्रभारी सहसंचालक, नगर रचना, यांजकडून

#### महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक प्रा.यो.अकोला-वाशीम-कलम-२० (४)-प्र.क्र.अ (१)सभा-१०-२०-सहसंचालक-८४२.—

ज्याअर्थी, अकोला-वाशीम प्रादेशिक योजना (यापुढे “उक्त प्रादेशिक योजना” असे संबोधिले आहे) शासनाच्या नगर विकास विभागाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ३७ वा) (यापुढे “उक्त अधिनियम” असे संबोधिले आहे) चे कलम १५ (१) अन्वये अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-२५०९-२०५-प्र.क्र. १०६-२००९-नवि-३०, दिनांक २३ एप्रिल, २०१२ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १५ जून, २०१२ पासून अंमलात आलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेतील मौजे चांदुर, ता.जि. अकोला येथील गट नं. २२/३ (भाग) मधिल २.०७ हे. आर, गट क्र. २३/३ क्षेत्र १.८२, गट क्र. २४/१ क्षेत्र ४.३० हे. आर, गट क्र. २४/२ क्षेत्र ४.४७ हे. आर असे एकूण १२.६६ हेक्टर क्षेत्र (यापुढे ज्यास “उक्त जमीन” असे संबोधले आहे) कृषी विभागात समाविष्ट आहे;

आणि ज्याअर्थी, शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५-प्र.क्र. ४९-१५-नवि-१३, दिनांक ०६-०५-२०१५ अन्वये उक्त अधिनियमाचे कलम-२० अन्वये फेरबदलाद्वारे मंजूर प्रादेशिक योजनेमधील जमीन वापर विभाग बदल करण्यासाठी विभागीय स्तरावर प्रस्ताव छाननी समिती (यापुढे “उक्त समिती” असे संबोधिले आहे) स्थापन करण्यात आली आहे;

आणि ज्याअर्थी, संचालक, नगर रचना महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी त्यांचे दिनांक ११-०४-२०१९ पत्रान्वये प्रस्तुत प्रकरणी विषयांकित फेरबदलाखालील जागेच्या उत्तरेकडून नदी वाहत आहे, तथापी, प्रादेशिक योजना नकाशावर या जागेलगत निळी व लाल पुररेषा दर्शविलेली नाही. त्यामुळे विकास परवानगी/अभिन्यास परवानगी घेण्यापूर्वी पाटबंधारे विभागाकडून या अनुषंगाने ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेणे आवश्यक राहिल, असा अभिप्राय दिला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता, अकोला, पाटबंधारे विभाग, अकोला यांनी त्यांचे दिनांक २७-०२-२०२० चे पत्रान्वये विषयांकीत जागेलगतचा विद्रुपा नदीवर दगडपारवा लघु प्रकल्प बांधण्यात आला आहे आणि हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यापासून कोणताही पूर आलेला नाही व पुराची संभावना नाहीशी झालेली आहे असे कळविले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, पाटबंधारे विभागाच्या वरीलप्रमाणे कळविल्यानुसार संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अभिप्रायाचे अनुपालन होते किंवा कसे व त्यानुसार प्रस्तावावरील पुढील कार्यवाही करावी किंवा कसे याबाबत संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मार्गदर्शन मागविण्यात आले ;

आणि ज्याअर्थी, दगडपारवा प्रकल्प झाल्यानंतर पुराची संभावना नाहीशी झाली आहे, ही बाब विचारात घेता कलम २० (४) नुसार फेरबदलाची कार्यवाही करण्यास प्रत्यावह नाही आणि जागेचे नदीलगतचे स्थान पाहता नदी पासून किती अंतरावर विकास परवानगी द्यावी याबाबत विकास परवानगी/अभिन्यास परवानगी देण्याचे वेळी मंजूर प्रादेशिक योजनेच्या तरतुदीनुसार तसेच पाटबंधारे विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्रानुसार कार्यवाही करणे आवश्यक राहिल, असे मार्गदर्शन संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी त्यांचे दिनांक १९-०५-२०१९ चे पत्रान्वये प्रस्तुत प्रकरणी दिले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त समितीचे दिनांक ९-०६-२०२० रोजी झालेल्या सभेमध्ये समितीचे सदस्यांचा सल्ला घेतल्यानंतर, शासनाने उपरोल्लेखित दिनांक ०६-०५-२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून उक्त अधिनियमाचे कलम-२० पोट-कलम (२) मधील तरतुदीनुसार उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त जमीन कृषीविभागातून वगळून खालील नमूद अटीच्या अधिन राहून रहिवास विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे समितीचे मत झाले आहे. (ज्यास यापुढे “प्रस्तावित फेरबदल” असे संबोधले आहे.) ;

- अट क्रमांक १ :—** फेरबदलाखालील क्षेत्राचा अभिन्यास करतांना त्यामध्ये अनिवार्य १०% खुल्या जागेव्यतिरिक्त १०% सुविधा क्षेत्र सोडण्यात यावे. (सदर क्षेत्र त्याच प्रयोजनार्थ जमीन मालक/विकासक यांना विकसित करता येईल.)
- अट क्रमांक २ :—** फेरबदलाखालील क्षेत्रात पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी जमीन मालक/विकासकाची राहिल. (जसे प्रवेशमार्ग, पाणीपुरवठा, विद्युत पुरवठा ईत्यादी)
- अट क्रमांक ३ :—** शासनाने आदेश क्र. टिपीएस-१८१५-प्र.क्र.४९-१५-नवि-१३, दिनांक ०६ मे, २०१५ व दिनांक ०४-०१-२०१६ अन्वये निर्धारित केल्याप्रमाणे अधिमूल्याचा भरणा करण्याची जबाबदारी जमीन मालक/विकासक यांची राहिल.
- अट क्रमांक ४ :—** विषयांकित जागेचे उत्तरेकडून विद्रुपा नदी वाहत आहे तथापी, प्रादेशिक योजना नकाशावर निळी व लाल पुररेषा दर्शविलेली नाही याबाबत तसेच नदीपासून किती अंतरावर विकास परवानगी द्यावी याबाबत विकास/अभिन्यास परवानगी देण्याचे वेळी मंजूर प्रादेशिक योजनेच्या तरतुदीनुसार तसेच पाटबंधारे विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेवून आवश्यक कार्यवाही करणे बंधनकारक राहिल.
- अट क्रमांक ५ :—** प्रस्तावाखालील जागेकरीता पाणी पुरवण्याची व्यवस्था उपलब्ध करून देणे बाबतचे प्रमाणपत्र संबंधित ग्रामपंचायत/जिल्हापरिषदेकडून प्राप्त करून घेणे आवश्यक राहिल.
- अट क्रमांक ६ :—** फेरबदलाखालील जमिनीत जर अभिन्यासात भूखंड पाडून विक्री करणे प्रस्तावित असेल तर अभिन्यासातील मूलभूत सुविधांचा विकास व भूखंड विक्रीसाठी खालीलप्रमाणे बंधने राहतील. जिल्हाधिकारी यांनी सदर बाबीवर नियंत्रण ठेवावे.
- |     |                                          |                                        |
|-----|------------------------------------------|----------------------------------------|
| (अ) | अभिन्यास अंतिम मंजूर झाल्यावर            | एकूण २५% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल.  |
| (ब) | सुमारे ४०% मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर  | एकूण ५०% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल.  |
| (क) | सुमारे ६०% मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर  | एकूण ७५% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल.  |
| (ड) | सुमारे ८०% मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर  | एकूण ९०% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल.  |
| (इ) | सुमारे १००% मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर | एकूण १००% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल. |
- अट क्रमांक ७ :—** तसेच जर अभिन्यासात समुह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर, जिल्हाधिकारी, अकोला यांनी विहित केल्यानुसार सर्व मुलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.

वरील कोणत्याही अटीचे उल्लंघन झाल्यास रेखांकन व अकृषक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहिल.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० पोट-कलम (३) च्या तरतुदीनुसार नोटीस क्रमांक प्रा.यो.अकोला-वाशीम-कलम-२०-प्र.क्र.ब(२)-सभा-७-१९-सहसंचायम-८४६, दिनांक ३०-०७-२०१९ अन्वये प्रस्तावित फेरबदलाबाबत जनतेकडून विहित मुदतीत सूचना/हरकती दाखल करणा-यांना सुनावणी देण्याकरिता व सदस्य सचिव, प्रस्ताव छाननी समिती, अमरावती यांना अहवाल सादर करण्याकरिता उक्त अधिनियमाचे कलम १६२(२) अन्वये अधिकारी म्हणून सहाय्यक संचालक, नगर रचना, शाखा कार्यालय, अकोला यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. (यापुढे उक्त अधिकारी असे संबोधले आहे);

आणि ज्याअर्थी, नियुक्त अधिका-याने त्यांच्या दिनांक १४-१०-२०२० च्या पत्रान्वये अहवाल सदस्य सचिव, प्रस्ताव छाननी समिती यांना सादर केलेला आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त समितीचे दिनांक ०९-०६-२०२० रोजी झालेल्या सभेमध्ये नियुक्त अधिका-याच्या प्राप्त अहवालानुसार उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त जमीन कृषी विभागातून वगळून वरील अटीच्या अधिन राहून रहिवास विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे समितीचे मत झाले आहे;

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या जमीन वापर बदलाच्या धोरणानुसार मौजे चांदूर, ता.जि. अकोला येथील गट क्र.२२/३ (भाग) मधील क्षेत्र २.०७ हे. गट क्र.२३/३ क्षेत्र १.८२ हे. गट क्र.२४/१ क्षेत्र ४.३० हे. गट क्र.२४/२ क्षेत्र ४.४७ हे. असे एकूण १२.६६ हेक्टर क्षेत्रासाठी जमीन मालक यांनी जमीन वापर बदलाचे अधिमूल्य दिनांक १०-०८-२०२० व १२-०८-२०२० ला शासकीय कोषागारात जमा केले असल्याने अट क्र.३ ची पूर्तता झाली आहे;

आणि ज्याअर्थी, शासनाचे निर्णय क्र. टिपीएस-१८१५-प्र.क्र. ४९-१५-नवि-१३, दिनांक ११-०६-२०१५ अन्वये संबंधित विभागीय सहसंचालक यांना उक्त अधिनियमाचे कलम २०(४) अन्वये अधिसूचना निर्गमित करण्याचे अधिकार प्रत्यायोजित करण्यात आलेले आहेत.

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम २० चे पोट-कलम (४) व त्याअनुषंगाने प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर करून सहसंचालक, नगर रचना, अमरावती विभाग, अमरावती उक्त जमिनीबाबत प्रस्तावित फेरबदलास पुढीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे व त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीची दिनांक २३-०४-२०१२ ची अधिसूचना पुढीलप्रमाणे सुधारित करण्यात येत आहे.

“उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदल नोंदीखालील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे.”

### नोंद

अकोला-वाशीम क्षेत्राच्या उक्त प्रादेशिक योजनेतील मौजे चांदूर, ता.जि. अकोला येथील गट क्र.२२/३ (भाग) क्षेत्र २.०७ हे. गट क्र.२३/३ क्षेत्र १.८२ हे. गट क्र.२४/१ क्षेत्र ४.३० हे. व गट क्र.२४/२ मधील ४.४७ हे. असे एकूण १२.६६ हेक्टर क्षेत्र कृषी विभागातून वगळून खालील अटीच्या अधिन राहून, भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे.

**अट क्रमांक १ :—** फेरबदलाखालील क्षेत्राचा अभिन्यास करतांना त्यामध्ये अनिवार्य १०% खुल्या जागेव्यतिरिक्त १०% सुविधा क्षेत्र सोडण्यात यावे. (सदर क्षेत्र त्याच प्रयोजनार्थ जमीन मालक/विकासक यांना विकसित करता येईल.)

**अट क्रमांक २ :—** फेरबदलाखालील क्षेत्रात पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी जमीन मालक/विकासकाची राहिल. (जसे प्रवेशमार्ग, पाणीपुरवठा, विद्युत पुरवठा इत्यादी)

**अट क्रमांक ३ :—** विषयांकित जागेचे उत्तरेकडून विद्रुपा नदी वाहत आहे तथापी प्रादेशिक योजना नकाशावर निळी व लाल पुररेषा दर्शविलेली नाही याबाबत तसेच नदीपासून किती अंतरावर विकास परवानगी द्यावी याबाबत विकास/अभिन्यास परवानगी देण्याचे वेळी मंजूर प्रादेशिक योजनेच्या तरतुदीनुसार तसेच पाटबंधारे विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र व पुररेषा दर्शविणारे नकाशे प्राप्त करून घेवून विकास परवानगीचे अनुषंगाने आवश्यक कार्यवाही करणे बंधनकारक राहिल.

**अट क्रमांक ४ :—** प्रस्तावाखालील जागेकरीता पाणी पुरवण्याची व्यवस्था उपलब्ध करून देणे बाबतचे प्रमाणपत्र संबंधित ग्रामपंचायत/जिल्हापरिषदेकडून प्राप्त करून घेणे आवश्यक राहिल.

**अट क्रमांक ५ :—** फेरबदलाखालील जमिनीत जर अभिन्यासात भूखंड पाडून विक्री करणे प्रस्तावित असेल तर अभिन्यासातील मूलभूत सुविधांचा विकास व भूखंड विक्रीसाठी खालीलप्रमाणे बंधने राहतील. जिल्हाधिकारी, अकोला यांनी सदर बाबीवर नियंत्रण ठेवावे.

|     |                                          |                                        |
|-----|------------------------------------------|----------------------------------------|
| (अ) | अभिन्यास अंतिमतः मंजूर झाल्यानंतर        | एकूण २५% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल.  |
| (ब) | सुमारे ४०% मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर  | एकूण ५०% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल.  |
| (क) | सुमारे ६०% मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर  | एकूण ७५% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल.  |
| (ड) | सुमारे ८०% मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर  | एकूण ९०% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल.  |
| (इ) | सुमारे १००% मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर | एकूण १००% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल. |

**अट क्रमांक ६ :—** तसेच जर अभिन्यासात समुह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर, जिल्हाधिकारी, अकोला यांनी विहीत केल्यानुसार सर्व मुलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.

वरील कोणत्याही अटीचे उल्लंघन झाल्यास रेखांकन व अकृषक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहिल.

उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे.

(१) सहसंचालक, नगर रचना, अमरावती विभाग, अमरावती.

(२) सहाय्यक संचालक, नगर रचना, अकोला शाखा, अकोला.

रा. दा. लांडे,

सदस्य सचिव,

प्रस्ताव छाननी समिती तथा

प्रभारी सहसंचालक, नगर रचना,

अमरावती विभाग, अमरावती.

अमरावती :

दिनांक १६ सप्टेंबर २०२०.

भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ९५.

MEMBER SECRETARY, ZONE CHANGE COMMITTEE OR INCHARGE JOINT DIRECTOR OF  
TOWN PLANNING

THE MAHARASHTRA REGIONAL & TOWN PLANNING ACT, 1966.

CORRIGENDUM

No.R.P.Akola-washim-Sect-20(4)-C.R.A(1)-Meeting-10-20-JDTPAMT-842.—

Whereas, the Regional Plan of Akola-washim Region (hereinafter referred in as the “said Regional Plan”) has been sanctioned by Government Urban Development Department under Section 15(1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as “the said Act”) *vide* Notification No. TPS-2509-2005-CR-106-UD-30, date 23<sup>rd</sup> April, 2012 and has come into force with effect from the 15<sup>th</sup> June, 2012;

And whereas, in the said Regional Plan, the land admeasuring 12.66 Ha. bearing Gat No. 22/3 (part) area 2.07 Ha., Gat No. 23/3 area 1.82 Ha., Gat no. 24/1 area 4.30 Ha., and Gat No. 24/2 area 4.47 Ha. of Mouje Chandur, Tal. and Dist. Akola, as shown on the Part Plan, (hereinafter referred to as the “said land”) is included in Agricultural Zone;

And whereas, Government has constituted Zone Change Committee (hereinafter referred to as “said committee”) *vide* Notification No. TPS-1815-C.R.49--15-UD-13, dated 6 May, 2015 for zone change proposals of sanctioned Regional Plans;

And whereas, Director Town Planning, M.S., Pune (hereinafter referred to as D.T.P.M.S. Pune) has given his opinion in the instant matter that as the Red Flood Line and the Blue Flood Line of the river adjacent to the said land is not shown on the Regional Plan Maps, a no objection certificate shall be obtained from the Irrigation Department before granting development permission/layout approval;

And whereas, Executive Engineer, Akola Irrigation Division, Akola has conveyed that the Dagadparwa Project is executed on the Vidrupa River which is adjacent to the said land and that after execution of this project there is no possibility of floods anymore.

And whereas, a guidance of the D.T.P.M.S., Pune was sought in light of the communication of the Irrigation Department as stated above, as to whether it satisfies the condition mentioned by him in the matter and whether the proposal of zone change be implemented,

And whereas, D.T.P.M.S., Pune has conveyed that after taking into consideration the fact that there is no possibility of floods due to execution of the Dagadparwa project on the said river, the zone change proposal may be implemented and that taking into consideration the location of the river, a decision regarding the distance of the said land from the river at which development permission/layout approval will be granted shall be taken at the time of scrutiny of the said development permission/layout approval proposal and that such permission shall be granted in accordance with the Regulations of the said Regional plan and in conformity with the no objection certificate of the Irrigation Department.

And whereas, said committee's meeting was held on 09-06-2020; and after consulting the committee members “said committee” is of the opinion., that the said land in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 20 of the said Act, should be deleted from Agricultural Zone and included in Residential Zone, subject to following conditions. (hereinafter referred to as the “Proposed Modification”

*Condition No. 1 :* While preparing the layout in respect of the said land under modification, apart from the compulsory 10% open space, 10% space shall be kept for public amenities. (This amenity space can be developed by the Land owner/Developer for the same purpose )

- Condition No. 2 :** It shall be the responsibility of the concerned Land Owner/Developer to provide all basic infrastructure *i.e.* access Roads, Water Supply, Power Supply etc. in the said land under modification.
- Condition No. 3 :** It shall be the responsibility of the Land Owner/Developer to pay Premium as decided by the Government *vide* order No. TPS-1815-C.R.49-15-UD-13, dated 6th May, 2015 and dated 04-01-2016. Also it is necessary to Pay Premium on the entire land under this proposal.
- Condition No. 4 :** Taking into consideration the location of the vidrupa river on the North of the said land and the fact that the corresponding Blue and Red Food lines have not been shown on the Regional Plan Maps, the decision regarding the distance of the said land from the existing river at which development permission/layout approval will be granted shall be taken at the time of detailed technical scrutiny of the proposal. Such permission/approval shall be granted strictly in accordance with the prevalent Development control Regulations of the said Regional plan and in conformity with the no objection certificate of the Irrigation Department and after taking into consideration the plans showing the flood line as approved by the Irrigation Department.
- Condition No. 5 :** Requisite certificate for necessary water supply arrangement shall be obtained from the concerned Grampanchayat/Zilla Parishad.
- Condition No. 6 :** If the said lands under modification are proposed to be developed by way of plotted layout, then sale of plots shall be monitored by the Collector, in relation to development of civic amenities as per the stages given below.—
- |     |                                             |                                                  |
|-----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| i   | After final approval of layout              | Sale of 25% of total Plots shall be permissible  |
| ii  | After completion of 40% of Civic Amenities  | Sale of 50% of total Plots shall be permissible  |
| iii | After completion of 60% of Civic Amenities  | Sale of 75% of total Plots shall be permissible  |
| iv  | After completion of 80% of Civic Amenities  | Sale of 90% of total Plots shall be permissible  |
| v   | After completion of 100% of Civic Amenities | Sale of 100% of total Plots shall be permissible |
- Condition No. 7 :** If Group Housing Scheme is proposed in the layout, then the occupancy certificate shall not be given unless civic amenities specified by the Collector are fully developed.

In case of non-compliance, layout Approval and Non-Agriculture permission shall be liable to be cancelled.

And whereas, the notice for the proposed Modification, under the powers conferred by Section 20 (3) of the said Act, was published by the member Secretary, Zone Change Committee, Amravati, *vide* Notice No. R. P Akola-Washim-Sect-20-C.R.B. (2)-meeting-7-19-JDTPAMT-846, dated 30th July 2019 inviting objections and suggestions from the general public, and the Assistant Director of Town Planning, Akola Branch was appointed as the officer (hereinafter referred to as the "said Officer) to hear the suggestions/objections received within the stipulated period only to submit his report on the same to the Member Secretary, Zone Change Committee, Amravati;

And whereas, the said Officer submitted his report to the Member Secretary, Zone Change Committee, Amravati *vide* his letter dated 14-10-2020;

And whereas, said committee's meeting was held on 09-06-2020 and after consulting the Member Secretary, Zone Charge Committee, Amravati & Committee Members on the report of the said officer, and the "said committee" is of the opinion., that the said land should be deleted from Agricultural Zone and included in Residential Zone, subject to certain conditions;

And whereas, Government by order No.TPS-1815-C.R.49-15-UD-13, Dt. 11-06-2015 has delegated power to the Joint Director of Town Planning of respective Division to notify under sub-section (4) of Section 20 of said act;

And whereas, as per zone change policy of Government, the owners of the said land have deposited the premium for the area 12.66 Ha. bearing Gat No. 22/3 (part) area 2.07 Ha. Gat No. 23/3 are 1.82 Ha, Gat No. 24/1 are 4.30 Ha, and Gat No. 24/2 area 4.47 ha of mouje Chandur in the Government Treasury Akola; *vide* date 10-08-2020 and 12-08-2020.

Now, therefore, in exercise of the power conferred under sub Section (4) of Section 20 of the said act, the joint Director of Town Planning, Amravati Division, Amravati hereby sanctions the proposed Modification in respect of the said land and for that purpose amends the above referred Notification dated the 23-04-2012 as follows;

"In the Schedule of Modification appended to the Notification dated 29<sup>th</sup> may 1993 sanctioning the said Regional Plan the following new entry shall be added after the last entry."

#### ENTRY

In the said Regional Plan, the land admeasuring 12.66 Ha. bearing Survey Gat No. 22/3 (part) area 2.07 Ha. Gat No. 23/3 are 1.82 Ha, Gat No. 24/1 are 4.30 Ha, and Gat No. 24/2 area 4.47 ha of mouje Chandur Bu, Tal. Akola, Dist. Akola is deleted from Agriculture Zone and included in Residential Zone subject to certain conditions.

- Condition No. 1 :* While preparing the layout in respect of the said land under modification, apart from the compulsory 10% open space, 10% space shall be kept for public amenities. (This amenity space can be developed by the Land owner/Developer for the same purpose )
- Condition No. 2 :* It shall be the responsibility of the concerned Land Owner/Developer to provide all basic infrastructure *i.e.* access Roads, Water Supply, Power Supply *etc.* in the said land under modification.
- Condition No. 3 :* Taking into consideration the location of the Vidrupa river on the North of the said land and the fact that the corresponding Blue and Red Food lines have not been shown on the Regional Plan Maps, the decision regarding the distance of the said land from the existing river at which development permission/layout approval will be granted shall be taken at the time of detailed technical scrutiny of the proposal. Such permission/approval shall be granted strictly in accordance with the prevalent Development control Regulations of the said Regional plan and in conformity with the no objection certificate of the Irrigation Department and after taking into consideration the plans showing the flood line as approved by the Irrigation Department.
- Condition No. 4 :* Requisite certificate for necessary water supply arrangement shall be obtained from the concerned Grampanchayat/Zilla Parishad.

**Condition No. 5 :** If the said lands under modification are proposed to be developed by way of plotted layout, then sale of plots shall be monitored by the Collector, in relation to development of civic amenities as per the stages given below.—

- |     |                                             |                                                  |
|-----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| i   | After final approval of layout              | Sale of 25% of total Plots shall be permissible  |
| ii  | After completion of 40% of Civic Amenities  | Sale of 50% of total Plots shall be permissible  |
| iii | After completion of 60% of Civic Amenities  | Sale of 75% of total Plots shall be permissible  |
| iv  | After completion of 80% of Civic Amenities  | Sale of 90% of total Plots shall be permissible  |
| v   | After completion of 100% of Civic Amenities | Sale of 100% of total Plots shall be permissible |

**Condition No. 6 :** If Group Housing Scheme is proposed in the layout, then the occupancy certificate shall not be given unless civic amenities specified by the Collector are fully developed.

In case of breach of any of the above conditions, layout Approval and Non-Agriculture permission shall be liable to be cancelled.

The copy of part plan showing the above sanctioned modification shall be kept open for inspection by general public during office hours on all working days for a period of one month at the following offices :—

- (1) The Joint Director of Town Planning, Amravati Division, Amravati.
- (2) The Assistant Director of Town Planning, Akola Branch, Akola.

Amravati :  
The 16<sup>th</sup> September 2020.

R. D. LANDE,  
Member Secretary,  
Zone Change Committee Or  
In-charge Joint Director of Town Planning,  
Amravati Division, Amravati.

भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ९६.

**अध्यक्ष, नगर परिषद, यांजकडून**

**महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ नुसार दिग्रस शहर मंजूर विकास योजनेतील किरकोळ फेरबदलाचा प्रारूप प्रस्ताव**

क्र. बांधकाम विभाग-नपदि-१४०७-२०२०.—

दिग्रस शहराकरीता मा. संचालक, नगर रचना विभाग, महाराष्ट्र शासन, पुणे यांचे अधिसूचना क्रमांक-डी.पी.दिग्रस (सु)-टि.पी.एस.-२७११-११७२-प्र.क्र.११-२०११ दिनांक ०३ एप्रिल २०१२ अन्वये विकास योजना मंजूर करण्यात आली आहे. तसेच सुधारित-२, दिनांक १५ मे २०१५ पासून योजना मंजूर करण्यात आली आहे.

दिग्रस नगर परिषदेने तिचे सभा दिनांक ०३ डिसेंबर २०१५ मधिल ठराव क्रमांक २८ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये दिग्रस शहराच्या विकास योजना आराखड्यात खालीलप्रमाणे किरकोळ फेरबदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

(१) दिग्रस शहर शे.स.नं.२०/३ मधिल आरक्षण क्र.१०, माध्यमिक शाळा व खेळाचे मैदान करीता आरक्षित असलेल्या शेतजमीन निवासी उपयोगी करणे.

वरिलप्रमाणे किरकोळ फेरबदलाचा प्रारूप आराखडा नगर परिषद कार्यालयात, कार्यालयीन वेळात कामकाजाच्या दिवशी पाहवयास उपलब्ध आहे. या बाबत कोणतही आक्षेप अथवा सुचना करावयाच्या असल्यास हा जाहीरनामा शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसाचे आंत मुख्याधिकारी, नगर परिषद, दिग्रस यांचेकडे लेखी स्वरूपात सादर करावा.

मुदतीत प्राप्त झालेल्या सूचनांवर आणि हरकतीवर उपरोक्त प्रस्ताव शासनकडे मंजूरीसाठी पाठविण्यापुर्वी विचार करण्यात येईल.

दिग्रस :

दिनांक ११ सप्टेंबर २०२०.

सदफजहा मो. जावेद,

अध्यक्ष,

नगर परिषद, दिग्रस.

भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ९७.

#### BY PRESIDENT, MUNICIPAL COUNCIL

#### NOTIFICATION OF MINOR MODIFICATION PROPOSED IN THE DEVELOPMENT PLAN OF DIGRAS TOWN U/S 37 OF MAHARASHTRA REGIONAL & TOWN PLANNING ACT, 1966.

No.PWD-MCD-1407-2020.—

The Development Plan of Digras town has been sanctioned by Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune *vide* their Notification No.D.P.-Digras (R)-TPS-2711-1172-no11-Ud-30 Dt. 30-04-2012.

The Municipal Council Digras *vide* its General Meeting Resolution No. 28, Dt. 03-12-2015 has resolved to make Minor Modification in the Development Plan of Digras Town u/s. 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 in the following reservation.

(1) Revenue Survey No. 20/3 Land reserved for School and Playground for is reserved Residential purpose.

The plan showing the above modification is kept open for public inspection in office of Municipal Council, Digras during any office day. The suggestions & objection on the above purpose from all or any person shall be received by the Chief Officer, Municipal Council, Digras within 30 days from the Publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette.

Any suggestion or objection on the above proposal so received will be considered before submitting it to the Government for sanction.

SADAFJAHAM D. JAVED,

President,

Municipal Council, Digras.

Digras :

The 11<sup>th</sup> September 2020.